रणजीत टाइम्स

इंदौर

शनिवार, 20 जून, 2026

वर्ष 02 | अंक 149 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

फार्म हाउस: आने वाले 10, 15 और 20 वर्षों का सुनहरा निवेश

आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हर व्यक्ति एक ऐसी जगह चाहता है जहाँ उसे शांति, स्वच्छ वातावरण और प्रकृति का साथ मिल सके। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में फार्म हाउस केवल एक निवेश नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल और भविष्य की सुरक्षा का माध्यम बनकर उभरा है।

फार्म हाउस क्यों है भविष्य का निवेश?

भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या, सीमित भूमि और तेजी से फैलते शहरों के कारण जमीन का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज जो क्षेत्र शहर से दूर दिखाई देते हैं, आने वाले वर्षों में वही क्षेत्र विकास के प्रमुख केंद्र बन सकते हैं।

10 वर्षों का विजन-अगले 10 वर्षों में शहरों का विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेजी से बढ़ेगा। नई सड़कें, हाईवे, औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन गतिविधियाँ आसपास की जमीनों की मांग बढ़ाएंगी। जो व्यक्ति आज फार्म हाउस में निवेश करता है, वह भविष्य में बढ़ती कीमतों और बेहतर लोकेशन का लाभ प्राप्त कर सकता है।

15 वर्षों का विजन-15 वर्षों बाद फार्म हाउस

केवल एक प्लॉट नहीं रहेगा, बल्कि परिवार के लिए एक Second Home बन जाएगा।

वीकेंड डेस्टिनेशन
परिवार के साथ छुट्टियाँ
ऑर्गेनिक खेती

होमस्टे एवं रिसॉर्ट जैसी आय के अवसर इस समय तक फार्म हाउस एक संपत्ति के साथ-साथ जीवनशैली का हिस्सा बन सकता है।

20 वर्षों का विजन-20 वर्षों बाद फार्म हाउस एक ऐसी विरासत बन सकता है जिसे आप अपनी अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। जब शहरों में भीड़, प्रदूषण और जगह की कमी बढ़ेगी, तब प्रकृति के बीच स्थित एक विकसित फार्म हाउस की उपयोगिता और महत्व और अधिक बढ़ सकता है। यह केवल जमीन नहीं होगी, बल्किः परिवार की पहचान,बच्चों के लिए सुरक्षित संपत्ति,रिटायरमेंट का शांत आशियाना,आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी विरासत

आर्थिक लाभ

फार्म हाउस कई प्रकार के लाभ प्रदान कर सकता हैः

जमीन के मूल्य में संभावित वृद्धि
किराये या पर्यटन आधारित आय के अवसर
ऑर्गेनिक खेती और बागवानी
भविष्य की पूंजी सुरक्षा
मुद्रास्फीति के प्रभाव से आंशिक बचाव
मानसिक और सामाजिक लाभ

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फार्म हाउस केवल निवेश नहीं, बल्कि मानसिक शांति का भी माध्यम है।

स्वच्छ हवा
प्राकृतिक वातावरण
तनावमुक्त जीवन
परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय

निष्कर्ष-फार्म हाउस खरीदना केवल जमीन खरीदना नहीं है, बल्कि अपने परिवार के भविष्य, जीवनशैली और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना है। आज का एक सही निर्णय आने वाले 20 वर्षों में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति और विरासत बन सकता है।

संदेश

"फार्म हाउस सिर्फ निवेश नहीं, प्रकृति से जुड़ने का अवसर, भविष्य की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत है।"

विजय कुमार
फार्म हाउस वाला ग्रुप
"अपना फार्म हाउस भी, अतिरिक्त आय भी"

पेरिस में PM मोदी ने गिनाईं 'नए भारत' की उपलब्धियां

पेरिस। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष, नवाचार, योग, डिजिटल तकनीक और वैश्विक व्यापार जैसे हर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने फुटबॉल से लेकर योग की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश अब केवल भागीदारी नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने

मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत ने दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता का नया परिचय कराया है। उन्होंने कहा कि आज भारत नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के सशक्त राजदूत हैं। उनकी उपलब्धियां दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा

विकसित भारत का संकल्प केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का साझा मिशन है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा तथा विश्व मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा।

'ऑपरेशन टाइगर' से हिली उद्धव सेना

शिंदे ने कैसे कराई सबसे बड़ी सियासी सेंध?

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शिवसेना (UBT) के कई सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री Eknath Shinde का कथित 'ऑपरेशन टाइगर' चर्चा का केंद्र बन गया है।

मुंबई। राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि इस रणनीति के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के दो-तिहाई सांसदों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, संगठन के भीतर असंतोष और नेतृत्व को लेकर मतभेद इस बगावत की प्रमुख वजहें रहीं। इनमें सांसद Sanjay Jadhav का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। चर्चा है कि कुछ सांसदों को विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया, जहां आगे की रणनीति पर विचार हुआ।

हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने इसे राजनीतिक दबाव और सत्ता के दुरुपयोग का परिणाम बताया है, जबकि शिंदे समर्थकों का कहना है कि सांसदों ने अपने राजनीतिक भविष्य और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। यदि यह टूट औपचारिक रूप लेती है, तो यह शिवसेना (UBT) के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं।

भारत-अमेरिका की डिफेंस साझेदारी से बढ़ी ताकत

स्वदेशी 155 मिमी तोप बनाएगी भारत फोर्ज

नई दिल्ली। भारत के रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती देने वाली एक अहम डील सामने आई है। रक्षा इकाई ने अमेरिकी रक्षा कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर अत्याधुनिक 155 मिमी मोबाइल आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित करेंगी, जो हर मौसम और दुर्गम इलाकों में सटीक निशाना साधने में सक्षम होगी।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह नई पीढ़ी की तोप लंबी दूरी तक मार करने, तेज तैनाती और उच्च गतिशीलता जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस होगी। इसका उपयोग भारतीय सेना के साथ-साथ वैश्विक रक्षा बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकेगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। इससे भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी और हथियार निर्यात के क्षेत्र में देश की स्थिति और बेहतर हो सकती है।

डील की घोषणा के बाद निवेशकों की नजरें भी भारत फोर्ज पर टिक गई हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश और निर्यात अवसरों का कंपनी को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। यह साझेदारी भारत को रक्षा उपकरणों के आयातक से निर्यातक देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

निकोटीन नहीं, तनाव है असली दुश्मन! AIIMS की रिसर्च में तंबाकू छुड़ाने का मिला योग मंत्र

नई दिल्ली। तंबाकू की लत से परेशान लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। (एम्स) नई दिल्ली की एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि योग तंबाकू की लत छोड़ने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। अध्ययन के अनुसार, नियमित योगाभ्यास से निकोटीन की तलब (क्रेविंग) कम होती है, तनाव घटता है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तंबाकू की लत केवल निकोटीन की वजह से नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे तनाव, चिंता, अवसाद, भावनात्मक अस्थिरता और सामाजिक दबाव जैसे कई कारण भी होते हैं। ऐसे में केवल दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना भी जरूरी है।

रिसर्च में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, उनमें तंबाकू सेवन की इच्छा अपेक्षाकृत कम होती है। योग शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाता है। इससे बार-बार तंबाकू सेवन करने की इच्छा पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अधिकांश लोग तनाव, गुस्सा, अकेलेपन या भावनात्मक दबाव के समय तंबाकू का सहारा लेते हैं। योग इस मानसिक चक्र को तोड़ने का काम करता है। प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यास मन को शांत करते हैं, जिससे व्यक्ति की आत्मनियंत्रण क्षमता बढ़ती है और नशे की लत से बाहर निकलने में मदद मिलती है। अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि देशभर में चल रहे तंबाकू मुक्ति अभियानों और डी-एडिक्शन कार्यक्रमों में योग को शामिल किया जाना चाहिए।

आपकी रसोई में छिपा है बीमारी का खतरा! ये छोटी-छोटी गलतियां बिगाड़ रही सेहत

नई दिल्ली। रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सेहत का आधार होती है। लेकिन रसोई में की जाने वाली कुछ आम गलतियां धीरे-धीरे गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि फूड सेफ्टी से जुड़ी लापरवाहियां फूड पॉइजनिंग, पेट के संक्रमण, एलर्जी और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। सबसे आम गलती है पके और कच्चे खाद्य पदार्थों को एक साथ रखना। कच्ची सब्जियों, मांस या अन्य खाद्य सामग्री में मौजूद बैक्टीरिया आसानी से पके भोजन तक पहुंच सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह बिना हाथ धोए खाना बनाना या परोसना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, कई लोग फ्रिज में भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित समझकर रखते रहते हैं। हालांकि तय समय से अधिक रखा गया भोजन बैक्टीरिया के पनपने का कारण बन सकता है। बचा हुआ खाना सही तापमान पर न रखना भी फूड पॉइजनिंग का बड़ा कारण माना जाता है। रसोई में गंदे कपड़े, स्पंज और कटिंग बोर्ड का उपयोग भी संक्रमण फैलाने का माध्यम बन सकता है। अक्सर लोग इन्हें नियमित रूप से साफ या बदलते नहीं हैं, जबकि इनमें बड़ी मात्रा में हानिकारक जीवाणु जमा हो सकते हैं।

खुले बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखना, एक्सपायरी डेट की अनदेखी करना और बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल में खाना पकाना भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। ऐसे तेलों में हानिकारक तत्व बनने लगते हैं, जो हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

महापौर परिषद के बड़े फैसले, श्मशान-कब्रिस्तानों में एक जैसी दरें लागू होंगी

इंदौर। शहर की व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में जहां कई पुराने और नए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, वहीं कुछ विवादित प्रस्तावों को फिलहाल रोक दिया गया। सबसे अहम फैसला शहर के 66 श्मशान और कब्रिस्तानों को लेकर लिया गया, जहां अब अंतिम संस्कार में उपयोग होने वाली सामग्री की दरें एक समान तय की जाएंगी। इसके साथ ही कचरा ट्रांसफर स्टेशन के मेंटेनेंस का ठेका निरस्त करने और नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के लिए बैंक लोन के साथ बॉण्ड जारी करने की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा हुई। महापौर परिषद की यह बैठक दोपहर बाद शुरू हुई और देर शाम तक चली। बैठक में कई प्रशासनिक, वित्तीय और जनहित से जुड़े मुद्दे सामने आए। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि शहर के अलग-अलग श्मशानों में अंतिम संस्कार के दौरान लकड़ी, कंडे और अन्य आवश्यक सामग्री के लिए अलग-अलग दरें वसूली जा रही हैं। कई स्थानों पर लोगों से तय दरों से अधिक राशि लेने के आरोप भी सामने आए थे। इसी को देखते हुए परिषद ने फैसला लिया कि अब शहर के सभी 66 श्मशान और कब्रिस्तानों के लिए एक समान दरें तय की जाएंगी।

महापौर परिषद के सदस्य मनीष शर्मा और अश्विन शुक्ल ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार की गई है। इसके तहत सभी श्मशानों और कब्रिस्तानों में एक ही दर पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि इन श्मशानों के संचालन और रखरखाव के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। वर्तमान में शहर के कई प्रमुख श्मशानों का संचालन सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं कर रही हैं और उनका प्रबंधन बेहतर माना जा रहा है। अब बाकी श्मशानों के लिए भी इसी मॉडल पर समितियां गठित की जाएंगी, ताकि व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।

कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर भी परिषद ने बड़ा फैसला लिया। शहर के 10 कचरा ट्रांसफर स्टेशनों के रखरखाव का ठेका अवि इंटरप्राइजेस को दिया गया था, लेकिन इसमें अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थीं। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रखरखाव के काम में गुणवत्ता और पारदर्शिता की कमी है। इसके बाद परिषद ने सर्वसम्मति से इस टेंडर को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह फैसला शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही रात में सड़कों की सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्विपिंग मशीनों के टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया। परिषद का मानना है कि इन व्यवस्थाओं में सुधार और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि शहर की सफाई व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सके। बैठक में नर्मदा परियोजना के चौथे चरण को लेकर भी अहम चर्चा हुई। नगर निगम इस परियोजना के लिए पहले 1530 करोड़ रुपए का बैंक लोन लेने की योजना बना रहा था। लेकिन अब वित्तीय रणनीति में बदलाव करते हुए निर्णय लिया गया है कि 1000 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 530 करोड़ रुपए बैंक लोन के जरिए जुटाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे निगम पर ब्याज का भार कम होगा और वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। नगर निगम इंजीनियरों के तबादलों और उनकी नियुक्ति में हुई देरी का मुद्दा भी बैठक में गरमाया।

कृषि महाविद्यालय इंदौर में छात्रों की समस्याओं को लेकर ABVP ने सौंपा ज्ञापन

राजेश धाकड़

इंदौर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) इंदौर द्वारा कृषि महाविद्यालय इंदौर के अधिष्ठाता को छात्रों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में RAWE बैच 2025-26 के लंबित भुगतान एवं किट वितरण, प्लेसमेंट सेल की स्थापना, कैंपस इंटरव्यू, रोजगार मेले, शिक्षकों की कमी दूर करने, लैब एवं प्रायोगिक सुविधाओं में सुधार, हॉस्टल व्यवस्था बेहतर करने, छात्रवृत्ति भुगतान तथा मेडिकल आधार पर परीक्षा अनुमति जैसी मांगें रखी गईं।

इस दौरान महानगर मंत्री देवेश गुर्जर, मालवा प्रांत सह मंत्री कुशल यादव, एग्रीविजन संयोजक निक्की धाकड़, नवलखा जिला संयोजक योग शर्मा, कृषि महाविद्यालय कार्यकारिणी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर सहित प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्रों के कई शैक्षणिक मुद्दों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर द्वारा सवाल पूछने पर अधिष्ठाता ने चुप्पी चुप्पी साधी, कई शैक्षणिक मुद्दों पर छात्रों के सवालों का संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय इंदौर के अधिष्ठाता डॉ. भरत सिंह ने ABVP द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों को स्वीकार करते हुए सात दिवस में समाधान का आश्वासन दिया। महानगर मंत्री देवेश गुर्जर ने कहा कि यदि सात दिवस में मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी।

जरूरतमंद बेटी के विवाह में आनंद विकास शिक्षा समिति बनी सहारा

दिव्यानंद अर्गल

भिंड। समाज सेवा और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्यरत आनंद विकास शिक्षा समिति ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। समिति के सदस्यों ने अटेर क्षेत्र के ग्राम हमीर सिंह का पूरा (पाली) पहुंचकर आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह अवसर पर सहयोग प्रदान किया और नवविवाहिता को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। समिति द्वारा नाथूराम प्रजापति की पुत्री कंचन को विवाह उपहार स्वरूप बजाज कंपनी की सिलाई मशीन भेंट की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस सहयोग का उद्देश्य केवल विवाह में सहभागिता निभाना नहीं, बल्कि नवविवाहिता को भविष्य में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना भी है। सिलाई मशीन के माध्यम से वह आवश्यकता पड़ने पर घर बैठे आय अर्जित कर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेगी। इस अवसर पर समिति के सदस्य दिनेश बौद्ध, राकेश सिंह पवैया, शीशपाल बौद्ध एवं राजेश सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने नवदंपति को शुभाशीष देते हुए उनके सुखमय, समृद्ध और सफल वैवाहिक जीवन की कामना की।

समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के साथ-साथ समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयासरत है। बेटियों के सम्मान, उनके उज्ज्वल भविष्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना संस्था की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर सामाजिक सहयोग एवं सेवा कार्य किए जाते हैं। समिति की इस मानवीय पहल की ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सेवा, सहयोग और सामाजिक एकजुटता की भावना को मजबूत करते हैं। साथ ही जरूरतमंद परिवारों को यह विश्वास भी दिलाते हैं कि समाज उनके साथ खड़ा है।

योग ने रची है भारतीय संस्कृति

परम पूज्य श्री माता जी

प्रागैतिहासिक काल से आज तक योग की पद्धति में नित नए आविष्कार नए परिवर्तन और समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य हुआ है परंतु योग का हमारी भारतीय संस्कृति से क्या संबंध है, सहजयोग की फाउंडर श्री माताजी निर्मला देवी जी ने योग और भारतीय संस्कृति के विषय पर व्यापक चर्चा की है। अगर यह जानना चाहें तो

पाते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार जो शांति का पोषण करता है वह योग की देन है कारण की जिस विश्व शांति का उद्घोषक भारत रहा है उसे भारतीयों ने बाहर नहीं अपने भीतर खोजा था। शांति की खोज पहले भीतर हुई और फिर वह बाहर फैला। यही परंपरा भारत में योग के द्वारा स्थापित है। प्रथम शरीर, मन, बुद्धि से होते हुए आत्मा तक पहुंचकर आत्मिक शांति की खोज की जाती है और तब मनुष्य विश्व शांति की बात कर सकता है। आक्रोशित आवेशित व्यक्ति की प्रतिक्रिया बढ़ती है। उसका उन पर नियंत्रण नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति विश्व शांति की बात करने का अधिकारी ही नहीं है। शांति का दूत वही बन सकता है जो जोड़ने की बात करे, एकात्मता की बात करे। इस प्रकार योग भारतीय संस्कृति में भीतर तक रचता बसता है, करुणा भारतीय संस्कृति का श्रृंगार है, यह समर्पण सिखाती है, यह अहंकार प्रति अहंकार भावनाओं के द्वंद से लड़ना सिखाती है इसमें माधुर्य का बड़ा महत्व है। यही आचरण की बात आती है कि यदि हमारा आचरण और व्यवहार मधुर और शांतिपूर्ण होगा तभी हम विश्वशांति के उद्घोषक हो सकेंगे ज्ञान को पाकर मस्तिष्क अहंकारी हो जाता है, प्रगल्भ मस्तिष्क बाहरी खोज के कारण अहंकार से भर जाता है। इसी मस्तिष्क की प्रगल्भता को, मस्तिष्क की गहनता को यदि बाहर से भीतर की ओर उन्मुख कर दें तो यह योग के आत्म साक्षात्कार की जीवंत घटना को प्रकट करती है। इसे ही सहज योग बड़ी सरलता से घटित करता है जिसमें श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा मानव जाति को सामूहिक आत्म साक्षात्कार देने की पद्धति अविष्कृत की गई है। सहज योग छोटी-छोटी प्रार्थना उसे मानव मन को बुद्धि की प्रगल्भता से हटाकर करुण और मधुर बनाकर आत्मा की ओर उन्मुख कर देता है। चित्त आत्मा में सरलता से स्थापित करने के लिए यह एक सुंदर और क्षणिक उपाय है, जिससे 10 से 15 मिनट में ध्यान की क्रिया घटित हो जाती है। कम समय में अधिक पाने का आधुनिक काल में सहजयोग से सुंदर कोई और तरीका नहीं है। आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने हेतु अपने नज़दीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं या वेबसाइट sahajayoga.org.in पर देख सकते हैं।

गौतम अडानी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में खकनार में रक्तदान शिविर, 48 यूनिट रक्त संग्रहित

अडानी फाउंडेशन और ACC सीमेंट की पहल, डीलर-सब-डीलर व शिल्पकारों ने किया रक्तदान

महेन्द्र मालवीय रणजीत टाईम्स

खकनार बुरहानपुर :- अडानी फाउंडेशन एवं अडानी सीमेंट (ACC Cement) के संयुक्त तत्वावधान में खकनार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अडानी फाउंडेशन के संस्थापक एवं उद्योगपति Gautam Adani के 24 जून को आने वाले 64वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित

किया गया। अडानी फाउंडेशन द्वारा देशभर में जरूरतमंद मरीजों की सहायता एवं सामाजिक सेवा के उद्देश्य से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में खकनार में आयोजित शिविर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बड़ी संख्या में अडानी सीमेंट के डीलर, सब-डीलर तथा शिल्पकार बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। शिविर के दौरान ब्लड बैंक की टीम की मौजूदगी में कुल 48 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान के बाद सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा अडानी सीमेंट की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

भूमिका इंटरप्राइजेस की रही महत्वपूर्ण भूमिका-कार्यक्रम को सफल बनाने में जिले के अधिकृत विक्रेता भूमिका इंटरप्राइजेस, डोईफोडिया एवं उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। शिविर के आयोजन, व्यवस्थाओं और रक्तदाताओं के पंजीयन में टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।

ये रहे उपस्थित-इस अवसर पर अडानी सीमेंट के एरिया सेल्स ऑफिसर (ASO) रोहन सपकाले, टेक्निकल सर्विस ऑफिसर (TSO) राहुल नाथ वर्मा तथा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव (CSE) मोहम्मद सोहेल सहित कंपनी के प्रतिनिधि एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

समाज सेवा की दिशा में सराहनीय पहल-रक्तदान शिविर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अडानी फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े ऐसे कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं, जिससे समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिल रहा है।

जल संकट के बीच यशवंत सागर बना सहारा, अब 10 टंकियों तक पहुंचेगा पानी

इंदौर। शहर में लगातार गहराते जल संकट के बीच नगर निगम अब Yashwant Sagar के पानी पर निर्भरता बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। अभी तक जहां यशवंत सागर के पानी से केवल 6 टंकियां भरी जाती थीं, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10 टंकियों तक जलापूर्ति करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए देवधरम फिल्टर स्टेशन स्थित ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। निगम का मानना है कि इससे शहर के पश्चिमी हिस्सों को बड़ी राहत मिल सकती है और नर्मदा पर दबाव भी कुछ कम होगा। फिलहाल शहर में Narmada River के तीन चरणों के जरिए जलूद से इंदौर तक करीब 450 एमएलडी पानी लाया जा रहा है। यह पानी शहर की विभिन्न टंकियों और सीधे पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। हालांकि नर्मदा का पानी इंदौर तक लाने में भारी खर्च आता है। इसके मुकाबले यशवंत सागर का पानी काफी सस्ता पड़ता है, इसलिए नगर निगम अब इस वैकल्पिक जल स्रोत का अधिकतम उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहा है।

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक अभी यशवंत सागर से प्रतिदिन 50 एमएलडी से अधिक पानी लिया जा रहा है। यदि ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ जाती है, तो यह मात्रा और बढ़ाई जा सकती है। इससे सुपर कॉरिडोर और उससे जुड़े नए विकसित क्षेत्रों तक भी यशवंत सागर का पानी पहुंचाया जा सकेगा। शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी को देखते हुए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले यशवंत सागर बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई थी, जिससे इसकी जल भंडारण क्षमता में भी इजाफा हुआ था। अब मानसून के दौरान यह बांध 19 फीट से अधिक तक भर जाता है और गर्मियों तक इसका पानी उपयोग में लिया जाता है। निगम का मानना है कि यदि इसका सुनियोजित दोहन किया जाए तो यह शहर के लिए मजबूत वैकल्पिक जल स्रोत साबित हो सकता है।

दूसरी ओर, शहर में जारी जल संकट के बीच जीआरपी लाइन में हुए लिकेज और मरम्मत कार्य के कारण आज भी कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रही। निगम के मुताबिक मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन तकनीकी कारणों से पानी का दबाव सामान्य होने में देरी हुई। इसके चलते आज सुबह करीब 20 टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर सकीं। Abhishek Sharma ने बताया कि कल डमी प्लेट हटाने का काम किए जाने के कारण नर्मदा के पहले और दूसरे चरण के पंप अस्थायी रूप से बंद करने पड़े थे। ये पंप रात में फिर शुरू हुए, लेकिन बिजलपुर स्थित कंट्रोल रूम तक पानी का पर्याप्त प्रेशर देर रात एक बजे के बाद बन सका। इसी वजह से सुबह की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई।

जिन टंकियों में पानी कम भरा गया उनमें अन्नपूर्णा, छत्रीबाग, राजमोहल्ला, योजना 103, लोकमान्य नगर, द्रविड़ नगर, महाराणा प्रताप, नरवल, कुशवाह मोहल्ला, बाणगंगा, सुभाष चौक, सदर बाजार, जिंसी हाट मैदान, मल्हार आश्रम, गांधी हॉल, भक्त प्रहलाद नगर, जयहिंद नगर और एमओजी लाइन क्षेत्र शामिल हैं। इन टंकियों में सामान्य स्तर से काफी कम पानी भरा गया, जिससे कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में जल संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर निगम को फिलहाल 700 से अधिक टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई करनी पड़ रही है। कई क्षेत्रों में नियमित सप्लाई नहीं होने के कारण टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है। ऐसे में निगम अब वाटर रिचार्जिंग, वाटर रियूज और अन्य जल संरक्षण परियोजनाओं पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लिम्बोदी तालाब और वीरगढ़ी हनुमान प्राचीन बावड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब गहरीकरण और संरक्षण कार्यों में श्रमदान भी किया। शहर में फिलहाल 10 से अधिक बड़े तालाबों और 250 से ज्यादा कुएं-बावड़ियों के संरक्षण, पुनर्जीवन और जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहर के लिए केवल एक जल स्रोत पर निर्भर रहना भविष्य में जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए यशवंत सागर जैसे वैकल्पिक स्रोतों का बेहतर उपयोग, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की योजनाएं शहर के लिए दीर्घकालिक समाधान साबित हो सकती हैं।

लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन बनेगा इंदौर का नया वैकल्पिक टर्मिनल

इंदौर। शहर के रेलवे ढांचे को मजबूत करने और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए Indian Railways ने लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को तेज कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, भवन हटने के बाद खाली हुई जगह पर अब दो अतिरिक्त ट्रैक और नए प्लेटफॉर्म के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे ने जुलाई के पहले सप्ताह तक नए ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बड़े हिस्से को तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का पूरा स्वरूप बदला जाएगा।

स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि यह भविष्य में इंदौर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रेलवे टर्मिनल बन सके। रेलवे का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ट्रेनों के संचालन में भी बड़ी राहत मिलेगी। इस परियोजना के तहत स्टेशन पर एक नया दो मंजिला भवन बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए आधुनिक टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, बेहतर प्रवेश और निकासी व्यवस्था के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 36 फीट चौड़ा फुटओवर ब्रिज भी तैयार किया जा रहा है। यह ब्रिज स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में आसानी होगी।

रेलवे स्टेशन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यहां तीन आधुनिक लिफ्ट भी लगाई जा रही हैं। इससे बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म को हाई लेवल बनाया जा रहा है, जिससे ट्रेनों में चढ़ने और उतरने में यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी। पुनर्विकास योजना के तहत भागीरथपुरा की ओर दो नए प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जा रहे हैं। इन प्लेटफॉर्मों के बनने से स्टेशन की ट्रेनों को संभालने की क्षमता बढ़ेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में कई ट्रेनों को यहां से संचालित करने की योजना है, जिससे इंदौर मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और ट्रेनों का दबाव कम किया जा सके। फिलहाल इंदौर का मुख्य स्टेशन यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेनों के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को वैकल्पिक टर्मिनल के रूप में विकसित करना रेलवे की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे मुख्य स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों में भी तेजी आएगी और संचालन में बाधा कम होगी।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि आगामी Simhastha को देखते हुए यह परियोजना और भी अहम हो जाती है। सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री इंदौर होकर गुजरते हैं। ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन और यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट केवल एक स्टेशन के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर के रेलवे नेटवर्क को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

आबकारी इंदौर की बड़ी कार्यवाही

कलेक्टर महोदय जिला-इंदौर , श्रीमान शिवम वर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिये निर्देशानुसार तथा *कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल एवम सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर के नेतृत्व में दिनांक-18/06/2026 वृत्त- काछी मोहल्ला में वृत- उप निरीक्षक भगवानदास अहरवार एव टीम के द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

आज की कार्यवाही में गश्त के दौराने कालका माता मंदिर के आगे कल्याण मिल तिराहा पर एक सुजुकी एक्सेस दो पहिया वाहन क्रमांक MP.09.ZJ.2325 को रोक कर तलाशी लेने पर कुल 300 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद की गई । मदिरा एवम सुजुकी एक्सेस दो पहिया वाहन जप्त कर कब्जे आबकारी लिया जाकर आरोपी (1) जय प्रकाश पिता नारायण, उम्र- 22 वर्ष, निवासी- श्याम नगर , सुखलिया आरोपी (2) आयुष नावरे पिता सुरेश , उम्र- 22वर्ष, निवासी- भगीरथ पुरा , इंदौर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क व 34(2)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।जप्ती का कुल बाजार मूल्य =/1,03,000/- रुपए रही। आज की कार्यवाही में आरक्षक सुश्री सीमा भूरिया ,आरक्षक योगेश मोहविया का सराहनीय योगदान रहा ।

मासूम को चाहिए 9 करोड़ का इंजेक्शन

हाई कोर्ट में उठे सवाल-क्या यही 'लाड़ली बहना' है?

स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही साढ़े 3 साल की मासूम बच्ची के इलाज को लेकर एक बार फिर न्यायालय में संवेदनशील सवाल उठा है। मामला Spinal Muscular Atrophy से पीड़ित बच्ची के उस इंजेक्शन से जुड़ा है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सुनवाई के दौरान Madhya Pradesh High Court में यह सवाल चर्चा में रहा कि क्या इस तरह की गंभीर स्थिति में राज्य और समाज की जिम्मेदारी सिर्फ नारों और योजनाओं तक सीमित रहनी चाहिए। अदालत ने भावनात्मक टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि क्या यह स्थिति 'लाड़ली बहना' जैसी योजनाओं की वास्तविक भावना को दर्शाती है, जहां हर जरूरतमंद बच्ची तक मदद पहुंचनी चाहिए।

परिजनों ने बताया कि अब तक उन्होंने समाज, दानदाताओं और ऑनलाइन फंडिंग के जरिए करीब साढ़े 7 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, लेकिन इलाज के लिए अभी भी बड़ी राशि की जरूरत है। परिवार लगातार आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। यह मामला न केवल चिकित्सा लागत की चुनौती को उजागर करता है, बल्कि गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकारी सहायता और स्वास्थ्य नीति पर भी सवाल खड़े करता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तय करते हुए मदद की संभावनाओं पर विचार जारी रखा है।

NEET परीक्षा में नकल रोकने पर कोर्ट की मुहर, टेलीग्राम बैन हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET पुनर्परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर लगाए गए केंद्र सरकार के अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया यह कदम आपात परिस्थितियों में आवश्यक और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप था।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्र और अन्य संवेदनशील सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लीक होने की आशंका थी। ऐसे में सीमित अवधि के लिए टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाना परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा के लिए जरूरी था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक हित और परीक्षा की विश्वसनीयता को देखते हुए सरकार को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं था, बल्कि केवल पुनर्परीक्षा के दौरान लागू किया गया अस्थायी उपाय था। इस फैसले को परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि प्रतिबंध से लाखों वैध उपयोगकर्ताओं को परेशानी हुई, लेकिन अदालत ने सरकारी कार्रवाई को उचित ठहराया।

राम मंदिर की दान पेटियों में गड़बड़ी का मामला, आखिर कैसे होती है करोड़ों के चढ़ावे की गिनती?

अयोध्या। राम मंदिर परिसर की दान पेटियों से चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं के बीच यह जानने

की उत्सुकता बढ़ गई है कि मंदिर में जमा होने वाले दान की गिनती आखिर कैसे की जाती है। मंदिर परिसर में स्थापित करीब 35 दान पेटियों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में नकद राशि, चेक और अन्य दान सामग्री जमा होती है। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान पेटियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत खोला जाता है। पेटियों से निकाली गई राशि को एक विशेष सुरक्षित कक्ष में ले जाया जाता है, जहां सीसीटीवी निगरानी और अधिकृत कर्मचारियों की मौजूदगी में गिनती की जाती है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए कई स्तरों पर निगरानी और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रहती है।

गिनती के दौरान नकदी को मशीनों की सहायता से अलग-अलग वर्गों में बांटा जाता है और उसका पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जाता है। इसके बाद राशि को बैंक में जमा कराया जाता है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि दान की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्त नियमों का पालन किया जाता है। हाल ही में सामने आए कथित चढ़ावा चोरी के मामले की जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिहार टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन

IAS अधिकारियों समेत कई ठिकानों पर SVU की छापेमारी

पटना। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित आईएएस अधिकारियों Yogesh Sagar और Abhilasha Sharma के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक निजी कंपनी के निदेशक के

आवास और अन्य संबंधित स्थानों पर भी दबिश दी गई। सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी कथित अनियमितताओं, टेंडर आवंटन में गड़बड़ी और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए की गई। SVU की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बिहार सरकार पहले ही दोनों अधिकारियों को निलंबित कर चुकी है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि सरकारी ठेकों के आवंटन में नियमों की अनदेखी कर कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसी आधार पर मामले की गहन जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाएगा। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस कार्रवाई से बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है तथा मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

सीमा पर फिर बढ़ा विवाद, BSF की कार्रवाई पर भारत-बांग्लादेश आमने-सामने

भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर एक बार फिर तनाव और विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी यह अंतरराष्ट्रीय सीमा दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील सीमाओं में गिनी जाती है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से होकर गुजरती है।

इस बीच Salman F Rahman (बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित) ने

संसद में बयान देते हुए भारतीय सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सीमावर्ती घटनाओं में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक असहजता बढ़ी है। वहीं Border Security Force ने अपने रुख में कहा है कि सीमा पर कार्रवाई पूरी तरह अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए की जाती है। BSF का दावा है कि जवान केवल नियमों और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही कार्रवाई करते हैं।

दोनों देशों के बीच यह मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन हाल के बयानों के बाद एक बार फिर राजनीतिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा प्रबंधन, संवाद और संयुक्त समन्वय के जरिए ही इस तरह के विवादों को कम किया जा सकता है। फिलहाल स्थिति पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की संभावना भी जताई जा रही है।

पानी के लिए सड़क पर उतरे किसान

खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में पानी की गंभीर किल्लत अब जनआक्रोश में बदलती नजर आ रही है। जिले के लाखी बिलाली क्षेत्र में शुक्रवार को पेयजल संकट और सूखे नदी-नालों से परेशान किसानों ने खंडवा-बड़ोदरा हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। चार गांवों के 250 से अधिक किसान सुबह से ही सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि लगातार शिकायतों और मांगों के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि लाखी बिलाली क्षेत्र के आसपास के गांवों में इस बार बारिश बेहद कम हुई है। इसका सीधा असर क्षेत्र की जल व्यवस्था पर पड़ा है। वेदा, कुंदा और खारक जैसी छोटी-बड़ी नदियां और नाले पूरी तरह सूख चुके हैं। इन जल स्त्रोतों पर ही गांवों की बड़ी आबादी और मवेशी निर्भर रहते हैं। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसलें भी पानी के अभाव में सूखने लगी हैं, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

सुबह करीब किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर हाईवे पर बैठ गए। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब दो घंटे तक खंडवा-बड़ोदरा हाईवे पूरी तरह जाम रहा। इस दौरान यात्री, ट्रक चालक और अन्य वाहन चालक परेशान होते नजर आए। कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना

करना पड़ा। हालांकि किसानों का कहना था कि जब तक उनकी बात प्रशासन नहीं सुनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से वे जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को क्षेत्र की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। गांवों में पेयजल संकट की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महिलाओं को सुबह-सुबह पानी भरने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। कई जगह टैंकरों के सहारे पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि एक-एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

किसानों ने यह भी बताया कि पानी की कमी का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुधन भी संकट में है। गांवों में बड़ी संख्या में मवेशी हैं, जिनके लिए पानी की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। कई तालाब और कुएं सूख चुके हैं। पशुपालकों का कहना है कि अगर जल्द कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो उनके सामने मवेशियों को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। चक्काजाम की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। काफी देर तक समझाइश का दौर चलता रहा। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और वैकल्पिक जल स्त्रोतों की तलाश की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। इसके बाद किसानों ने जाम समाप्त किया और यातायात फिर से सुचारू हो सका।

स्थानीय किसानों का कहना है कि हर साल गर्मियों और कम बारिश के समय यह संकट सामने आता है, लेकिन स्थायी योजना के अभाव में समस्या जस की तस बनी रहती है। उनका कहना है कि सरकार को क्षेत्र में जल संरक्षण, नए जल स्त्रोतों के निर्माण और नहर परियोजनाओं पर गंभीरता से काम करना चाहिए। केवल अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में इस बार कमजोर मानसून और जल प्रबंधन की कमी के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और पारंपरिक जल स्त्रोतों का संरक्षण पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और कृषि आधारित क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। खरगोन जिले में किसानों का यह आंदोलन प्रशासन के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है। किसानों ने साफ कहा है कि यदि पानी की व्यवस्था जल्द नहीं हुई, तो वे फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन ने राहत देने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है। क्योंकि पानी केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि जीवन का आधार है और जब यही संकट में पड़ जाए तो आक्रोश का सड़क पर उतरना तय माना जाता है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर
रेलवे की नजर, देश के 72 स्टेशनों के सर्वे में उज्जैन भी शामिल

रेल मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए देश के 72 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान स्टेशन परिसरों में सुचारू संचालन बनाए रखना है। इस सूची में मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण स्टेशन भी शामिल किए गए हैं—उज्जैन रेलवे स्टेशन और सीहोर रेलवे स्टेशन। उज्जैन स्टेशन पर विशेष रूप से महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक के कारण पूरे वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन, महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों के दौरान यहां यात्री दबाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

इसी स्थिति को देखते हुए रेलवे ने यह अध्ययन शुरू किया है, जिसमें यात्री प्रवाह, प्लेटफॉर्म की क्षमता, प्रवेश और निकास व्यवस्था तथा आपातकालीन निकासी प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन के आधार पर रेलवे भविष्य में स्टेशन ढांचे में सुधार, अतिरिक्त प्रवेश द्वार, डिजिटल निगरानी प्रणाली और होल्डिंग एरिया जैसी सुविधाएं विकसित कर सकता है।

प्यासे बाघों का बढ़ता खतरा
जल स्त्रोत सूखे तो जंगल छोड़ आबादी में पहुंच रहे वनराज, 5 साल में 380 मौतें

भोपाल। मध्य प्रदेश में जल स्त्रोतों के सूखने और मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने से बाघों के हमलों की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। पिछले पांच वर्षों में राज्य में बाघों के हमलों में 380 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि गर्मी के मौसम में जंगलों के भीतर पानी की कमी होने पर बाघ और अन्य वन्यजीव भोजन एवं पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, कई वन क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्त्रोतों का स्तर लगातार घट रहा है। इसका असर वन्यजीवों के व्यवहार पर पड़ रहा है। पानी और शिकार की तलाश में बाघ गांवों और खेतों के नजदीक पहुंच रहे हैं, जिससे इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव बढ़ रहा है। Madhya Pradesh देश में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य माना जाता है। वन विभाग कृत्रिम जल स्त्रोत विकसित करने, जलाशयों का संरक्षण करने और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने जैसे कदम उठा रहा है। इसके बावजूद कई इलाकों में खतरा बना हुआ है।

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में जल संरक्षण, आवास प्रबंधन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाए बिना इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

इसराइल को जेडी वेंस की दोटूक सलाह

'अपने सबसे बड़े सहयोगी को नाराज मत करो'

वॉशिंगटन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति J. D. Vance ने इसराइल को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि उसे अपने सबसे करीबी और महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका के हितों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वेंस की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज है।

जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल को अपने फैसलों में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो उसके प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंधों को प्रभावित करें। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका लंबे समय से इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है और

दोनों देशों के रिश्ते क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके बयान को अमेरिका की ओर से इसराइल के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वॉशिंगटन चाहता है कि क्षेत्र में तनाव और न बढ़े तथा कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं बनी रहें।

हालांकि इसराइल की ओर से वेंस के बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस टिप्पणी ने अमेरिका-इसराइल संबंधों और मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों देशों के रुख पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी रहेगी।

राज्यसभा में NDA का दम, 27 में 19 सीटें जीतकर बढ़ाई ताकत; INDIA गठबंधन पिछड़ा

नई दिल्ली। 10 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 19 सीटें जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। इस प्रदर्शन के बाद उच्च सदन में एनडीए दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के और करीब पहुंच गया है। वहीं विपक्षी INDIA गठबंधन को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा में बढ़ता संख्या बल केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में मददगार साबित हो सकता है।

कई ऐसे विधेयक, जो पहले संख्या के अभाव में अटक जाते थे, अब उनके लिए रास्ता आसान हो सकता है। चुनाव परिणामों ने यह भी संकेत दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की राजनीतिक पकड़ मजबूत बनी हुई है। दूसरी ओर विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कमी और क्षेत्रीय समीकरणों का असर कई राज्यों में देखने को मिला। यही

वजह रही कि INDIA गठबंधन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इन नतीजों का असर केवल राज्यसभा की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी संसदीय सत्रों और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों पर भी दिखाई देगा। परिणामों को सत्ता पक्ष के लिए बड़ी उपलब्धि और विपक्ष के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

योग दिवस की बैठक पर केरल में टकराव, राज्यपाल और कांग्रेस सरकार आमने-सामने

तिरुवनंतपुरम। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर केरल में राज्यपाल Rajendra Vishwanath Arlekar और कांग्रेस नीत सरकार के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्यपाल द्वारा अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाए जाने पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक तैयारियों और सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करना निर्वाचित सरकार का अधिकार है।

ऐसे मामलों में राज्यपाल की सीधी भूमिका नहीं होनी चाहिए

सरकार ने इस कदम को संवैधानिक परंपराओं के विपरीत बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने की बात कही है। वहीं राजभवन का पक्ष है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और इसके सफल आयोजन के लिए समन्वय एवं तैयारियों की समीक्षा करना आवश्यक था। राज्यपाल ने अधिकारियों से

कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली और बेहतर आयोजन पर जोर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद केवल योग दिवस तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे अधिकार क्षेत्र के मतभेद का हिस्सा है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर संवैधानिक मर्यादाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर बहस छेड़ दी है।

कश्मीर में पर्यटक वाहनों पर बवाल, PDP और BJP में तेज हुई सियासी जंग

कश्मीर में पर्यटक वाहनों के संचालन को लेकर उठी मांग ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है।

श्रीनगर। स्थानीय टैक्सी यूनियनों द्वारा बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर नियंत्रण की मांग के बाद People's Democratic Party (PDP) और Bharatiya Janata Party (BJP) आमने-सामने आ गई हैं।

पीडीपी का कहना है

पर्यटन से होने वाले आर्थिक लाभ का बड़ा हिस्सा स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए।

पार्टी के अनुसार

बाहरी वाहनों की बढ़ती संख्या से

स्थानीय टैक्सी चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार को स्थानीय हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

वहीं भाजपा ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा

ऐसे प्रतिबंधों से जम्मू-कश्मीर की पर्यटन-अनुकूल छवि प्रभावित हो सकती है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि पर्यटकों के लिए अतिरिक्त बाधाएं खड़ी करना प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मुद्दे पर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी बंटे नजर आ रहे हैं। कुछ संगठन स्थानीय रोजगार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य का कहना है कि किसी भी फैसले से पर्यटकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल यह मुद्दा रोजगार, पर्यटन और स्थानीय अधिकारों को लेकर कश्मीर की राजनीति का नया केंद्र बन गया है।